



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० ५७]

नई दिल्ली, बुधवार, फरवरी १७, १९८२/माघ २८, १९०३

No. ५७] NEW DELHI, WEDNESDAY, FEBRUARY 17, 1982/MAGHA 28, 1903

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संलग्न दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में
रखा जा सके

Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate
compilation

पृष्ठ संख्या

प्रकाशन

नई दिल्ली, १७ फरवरी, १९८२

कांग्रेस ८३(प्र).—यत् लोकसभा ने यह संकल्प पारित किया है कि

(१) गांधी शांति प्रतिष्ठान,

(२) गांधी स्थारक निधि,

(३) अखिल भारतीय मर्बे मेवा संघ; और

(४) तीन उपर्युक्त संगठनों से निकट रूप में सबद्ध अन्य संगठनों
के सार्वजनिक महाल के निश्चित मामले अथवा कार्यकरण और कार्य-
कालीनों जिनके अन्तर्गत प्रकाशन और स्रोत हैं तथा निधियों के दुरुपयोग
की जाच करने के प्रयोजन के लिए एक जांच आयोग नियुक्त किया
जाए।

प्रौढ़ यम. केन्द्रीय सरकार की यह राय भी है कि सार्वजनिक महाल
के अन्य निश्चित मामले, अथवा, ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक अभियानों के मामले और इसमें निकट रूप से सबद्ध अन्य संगठनों के कार्यकरण
और कार्यकालीनों की जिनके अन्तर्गत प्रकाशन और स्रोत हैं तथा निधियों
के दुरुपयोग की जाच करने के प्रयोजन के लिए एक जांच आयोग नियुक्त
करना आवश्यक है।

यत् वैल्ड्रीय सरकार, जांच आयोग अधिनियम, १९५२ (१९५२
का ६१) की धारा ३ द्वारा प्रदत्त गविनियों का प्रयोग करने हुए, एवं
जांच आयोग नियुक्त करती है जिसमें उच्च न्यायालय के न्यायाधीण
न्यायमूलि श्री पी०डी० कुडाल होंगे।

2 आयोग के निर्देश-निर्बंधन निम्नलिखित होंगे—

(क) (१) गांधी शान्ति प्रतिष्ठान,

(२) गांधी स्थारक निधि;

(३) अखिल भारतीय सभे सेवा संघ,

(४) ग्रामीण विकास के लिए स्वैच्छिक अभियानों का संगम, और

(५) उपर्युक्त संगठनों से निकट रूप में सबद्ध अन्य संगठनों के,

यह अधिकारित करने के लिए किया उन्होंने अन्य लक्ष्यों और उद्देश्यों
के अनुरूप कार्य किया कार्यकरण और कार्यकालीनों की, जिनमें प्रकाशन भी
है जांच करना;

(ख) उपर्युक्त संगठनों की निधियों के स्रोतों की जांच करना;

(ग) उक्त संगठनों द्वारा, उनके स्रोतों और उद्देश्यों के संदर्भ में
निधियों के उपयोग की रोति और उनके दुरुपयोग की यदि
कोई हो, जांच करना; और

(घ) किसी भी ऐसे मामले की जो उपर्युक्त मामलों से आनुरूपिक
या भुसगत हो जांच करना।

3 आयोग का मुख्यालय नई दिल्ली से होगा।

4. आयोग प्रधानी जांच पूरी करेगा और अपनी रिपोर्ट केन्द्रीय सरकार
को ३१ जुलाई, १९८२ को या इसके पूर्व देगा और ऐसे मामले या मामलों
में संवेदन ऐसी अनरिम रिपोर्ट या रिपोर्टें भी जो आयोग उचित समझे
दे सकेंगी।

5. और यह केंद्रीय सरकार की, की जाने वाली जांच के स्वरूप और भास्ते की अन्य परिवर्तियों को ध्यान में रखते हुए यह है कि जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) को भारा 5 की उपधारा (2), उपधारा (3), उपधारा (4) और उपधारा (5) के सभी उपबंध आयोग को लागू होने चाहिए, केंद्रीय सरकार, उक्त धारा 5 की उपधारा 1 द्वारा, प्रवत शक्तियों क, प्रयोग करते हुए नियम देती है कि उक्त उपधारा (2), (3), (4) और (5) के गमा उपबंध आयोग को लागू होंगे।

[I/12014/4/81-आइएस० (31-II)]

जो० एम० ग्रेवाल मंत्रीकृत सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 17th February, 1982

S.O. 83(E).—Whereas the House of the People have resolved that a Commission of Inquiry be appointed for the purpose of making an inquiry into a definite matter of public importance, namely, the working and activities, including publications and sources and misuse of funds, of—

- (1) Gandhi Peace Foundation ;
- (2) Gandhi Samarak Nidhi ;
- (3) All India Sarva Sewa Sangh ; and
- (4) Other organisations closely connected with the three above-mentioned organisations ;

And whereas the Central Government is also of opinion that it is necessary to appoint a Commission of Inquiry for the purpose of making an inquiry into another definite matter of public importance, namely the working and activities including publications and sources and misuse of funds of the Association of Voluntary Agencies for Rural Development and other organisations closely connected with it ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby appoints a Commission of Inquiry consisting of Shri Justice P. D. Kudal, a Judge of the Rajasthan High Court.

2. The terms of reference of the Commission shall be as follows :—

- (a) to inquire into the working and activities, including publications, of—
 - (1) Gandhi Peace Foundation ;
 - (2) Gandhi Samarak Nidhi ;
 - (3) All India Sarva Sewa Sangh ;
 - (4) Association of Voluntary Agencies for Rural Development ; and
 - (5) Other organisations closely connected with the above-mentioned organisations ;

to determine whether they acted in conformity with their aims and objects ;

- (b) to inquire into the sources of funds of the organisations referred to above ;
- (c) to inquire into the manner of utilisation of funds and misuse thereof, if any, by the said organisations, with reference to their aims and objects ; and
- (d) to inquire into any such matter as may be incidental or relevant to the above-mentioned matters

3. The headquarters of the Commission shall be at New Delhi.

4. The Commission will complete its inquiry and report to the Central Government on or before the 31st July, 1982 and may also submit such interim report or reports concerning such matter or matters, as it may think fit.

5. And whereas the Central Government is of opinion, having regard to the nature of the inquiry to be made and other circumstances of the case, that all the provisions of sub-section (2), sub-section (3), sub-section (4) and sub-section (5) of section 5 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), should be made applicable to the Commission, the Central Government hereby directs, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of the said section 5, that all the provisions of the said sub-sections (2), (3), (4) and (5) of that section shall apply to the Commission.

[I/12014/4/81-IS(D. II)]
G. S. GREWAL, Jt. Secy.